सचिव (श्रम)	सदस्य
सचिव (शिक्षा)	सदस्य
आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
श्रम मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला श्रम प्रतिनिधि	सदस्य
औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित किया जाने वाला नियोक्ता प्रतिनिधि	सदस्य
सरकार से बाहर के दो विशिष्टि व्यक्ति जिन्हें प्रबंध, औद्योगिक अथवा श्रमिक संबंधी के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव अथवा विशेषज्ञता प्राप्त हो	सदस्य
ऊपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	कार्यकारी निदेशक

मध्य प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना

1450. **श्री अजीत जोगी :**
चौधरी हरि सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में नए उद्योगों की स्थापना करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है,

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, और

(घ) मध्य प्रदेश तथा अन्य पिछड़े आदिवासी तथा अविकसित राज्यों में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कौन-कौन सी नई पहल की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य औद्योगिक विकास निगम से 1990–1993 (जून, 1993 तक) के दौरान औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए 5 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

प्रस्तावों की संख्या		निपटान की स्थिति
1990	3	अस्वीकृत
1991	2	1. अस्वीकृत 1. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
1992	शून्य	
1993	शून्य	

(घ) नई औद्योगिक नीति के अधीन औद्योगिक विकास करना राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रोत्साहनों इत्यादि जैसे उपाय करें।

देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक विकास केन्द्र योजना है। इसके अलावा पहाड़ी, दूरस्त और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक परिवहन राजसहायता योजना भी है।